where we do not have the facilities to give it to them and where we do not have the regular health workers to take care of the routine immunization. All those areas have been given due consideration in the Mission Indradhanush. We have not left out the left-outs. This programme undertakes only those immunizations where we send our health workers specially to those areas and See to it that those who are left out are covered. So, tribal areas are very much in focus. And, we are getting very good results in the tribal areas.

SHRI AJAY SANCHETI: Sir, I compliment the Minister for his detailed reply. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के और specially महाराष्ट्र के कुपोषणग्रस्त इलाकों को fully immunize करने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाया जा रहा है?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, मैंने पहले ही कहा कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, चाहे वे महाराष्ट्र के हों या बाकी जगहों के हों, वे हमारे मैप पर हैं। इतना ही नहीं, मान लीजिए कि जहां कोई हेल्थ वर्कर तीन महीने से absent रही है या कहीं पर पोस्टिंग नहीं हुई है, उन एरियाज़ को हम लोगों ने special attention में लिया है और जहां उनकी vaccination नहीं हुई थी, उनको लिया है। इस तरह से महाराष्ट्र के भी ऐसे सभी एरियाज़ को इसके तहत लिया गया है।

जहां तक "जीका" वायरस के बारे में आपने पूछा, इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकली है, इसलिए अभी हमें इसके preventive part पर ही वर्क करना पड़ेगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Viplove Thakur. Women's Day question!

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, माननीय मंत्री जी इस बात को पूरी तरह से जानते हैं कि देश में टीबी बहुत फैल रहा है। हमारे देश में इसका प्रकोप दोबारा पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या टीबी की vaccine pregnant woman और बच्चों को दी जा रही है और इसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? क्या इसके लिए vaccination है? Pregnant women और बच्चों में इसको prevention के लिए क्या किया जा रहा है?

श्री जगत प्रकाश नड्डाः सर, pregnant woman के लिए हमारा neo-natal tetanus का इंजेक्शन है, जिसे हम दे रहे हैं। जहां तक tuberculosis का सवाल है, इस तरीके का कोई इंजेक्शन pregnant woman को नहीं दिया जाता है। हम BCG का इंजेक्शन देते हैं, which includes tuberculosis, which is given to the children, not to the pregnant mothers.

[The Questioner (SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN) was absent.]

बिहार को योजनागत धनराशि जारी किया जाना

*111. **श्रीमती कहकशां परवीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बिहार के लिए निर्धारित योजनागत धनराशि में से काटी गई राशि को जारी करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्यमान पद्धति के अनुसार, योजना स्कीमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों को केन्द्रीय धनराशि, संबंधित स्कीमों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों, सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार जारी की गई धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने और केन्द्र सरकार के पास सकल बजट सहायता के अंदर धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए जारी की जाती है और जो धनराशि अप्रयुक्त रहती है उसे अगले वर्ष दिए जाने वाले अनुदानों में समायोजित किया जाता है। इन कारकों के आधार पर, बिहार सहित राज्यों को समय-समय पर धनराशि जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार स्कीम के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों एवं केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के तहत भी धनराशि प्राप्त होती है।

14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय करों की निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किए जाने के रूप में भारी वृद्धि की गई है। 13वें वित्त आयोग (2010-11 से 2014-15 तक) द्वारा 158341.22 करोड़ रुपए के अनुमानित कर अंतरण के मुकाबले में 14वें वित्त आयोग द्वारा 2015-20 की अवधि के लिए बिहार राज्य के लिए अनुमानित कुल कर अंतरण 381592.27 करोड़ रुपए है। इससे कर अंतरण में 141% की वृद्धि दिखाई देती है। उच्चतर कर अंतरण से राज्य को अपनी प्रासंगिक जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार स्कीमों के वित्त पोषण और रूपरेखा तैयार करने में अधिकाधिक स्वायत्ता मिलेगी।

Release of plan funds for Bihar

†*111. SHRIMATI KAHKASHAN PERWEEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government proposes to release the amount deducted from the Plan funds earmarked for Bihar; and

(b) if so, by when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per the extant practice, release of Central funds to the States under various programmes including Plan Schemes are governed by prescribed guidelines of the respective schemes, submission of Utilization Certificates for funds released as per General Financial Rules (GFR) and availability of funds within Gross Budgetary Support (GBS) with the Union Government and the funds that remain unutilized is adjusted towards

†Original notice of the question was received in Hindi.

the grants payable during the next years. Based on these factors, funds are released to the States including Bihar from time to time. Further, States also received funds under various Centrally Sponsored Schemes (CSS) and Central Sector Schemes (CS) as per the prescribed scheme guidelines framed by the concerned line Ministries/Departments.

Consequent to the recommendations of 14th Finance Commission (FFC), share of States in the net proceeds of union taxes has been significantly enhanced from 32% to 42%. The total tax devolution to Bihar State for the period 2015-20 estimated by the 14th Finance Commission (FFC) is at ₹ 381592.27 crore against the estimated tax devolution of ₹ 158341.22 crore by 13th FC (2010-11 to 2014- 15). This shows an increase of 141% increase in tax devolution. The higher tax devolution will allow the State greater autonomy in financing and designing of schemes as per their contextual need and priority of the State.

MR. CHAIRMAN: Question No. 111. Questioner not present, let the question be answered.

डा. अनिल कुमार साहनीः सभापति महोदय, जो जवाब दिया गया है, वह बिहार की काटी गई राशि के बारे में है। यह सच है कि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही धनराशि भेजते हैं, मगर मैं आपसे इससे अलग प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने चुनावी भाषण में 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, सवा सौ करोड़ देने की बात कही थी, उसके लिए पूरे बिहार के लोग आपकी ओर आशा से देख रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह पैसा, यानी 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, या सवा सौ करोड़ एकमुश्त भेजना चाहते हैं या किस्तों में भेजना चाहते हैं? आप यह बताने का कष्ट करें, क्योंकि बिहार की जनता आशा से आपकी ओर देख रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह स्पष्ट करें कि यह केवल एक चुनावी जुमला था या सही में यह पैसा जाने वाला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): चेयरमैन सर, आपको मालूम है कि जब सरकार में, खासकर माननीय प्रधान मंत्री जी इस प्रकार से बात करते हैं और जनता को बताते हैं और उनकी तरफ से जब 1 लाख 25 हजार करोड़ का कमिटमेंट दिया गया है तो उस कमिटमेंट को पूरी तरह से निभाया जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री जी की तरफ से यह जो कमिटमेंट था, यह अभी भी बरकरार है और इसे पूरे तरीके से निभाया जाएगा। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...*(Interruptions)*...

श्री जयंत सिन्हाः चेयरमैन सर, आपको यह भी मालूम है कि माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उनको सरकार की पूरी जानकारी है। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... You have put your question. ...*(Interruptions)*...

श्री जयंत सिन्हाः उनको मालूम है कि जब सरकार की तरफ से धनराशि जाती है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और रिलीज़ अमाउंट के सब तरीके से प्रमाण आने के बाद ही ये फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं। यह 1 लाख 25 हजार करोड़ का जो मामला है, मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय

सदस्य ने पहले भी प्रश्न पूछा था। उन्होंने यह प्रश्न पूछा था कि जो devolution का पैसा है, जो 1 लाख 25 हजार करोड़ है, यह अलग है या नहीं है। मैं उनको भी स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूं और माननीय सदस्य को भी बताना चाहता हूं कि जो 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की बात हुई थी, वे सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के तहत चाहिए, चाहे वे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से हों, चाहे वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री से हों, इन सबको मिलाकर 1 लाख 25 हजार करोड़ का पैकेज बनाया गया था। इस पैकेज की मॉनिटरिंग पी.एम.ओ. से हो रही है, हमारे वित्त मंत्रालय से भी हो रही है। आप सब लोगों को विश्वास होना चाहिए कि अगर हम सब लोगों ने यह बात कही है, तो हम इस बात को पूरे तरीके से निभाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग भी होगी और इसका बिहार की जनता को पूरा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये स्कीम्स पेपर्स पर ही रहेंगी? **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please. It is not your question. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: सर, इसकी कोई समय-सीमा निश्चित होनी चाहिए। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: No; this is not your question. ...*(Interruptions)*... This is not your question. ...*(Interruptions)*... Prem Chandji, please. ...*(Interruptions)*... Shri Gulam Rasool Balyawi.

श्री गुलाम रसूल बलियावी: सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आपकी नीयत है कि देंगे। कब देंगे, समय निर्धारित नहीं है, लेकिन बिहार के पुल और एन.एच. के रिपेयरिंग के लिए, जबकि केन्द्र सरकार ने इस बात को स्वीकार भी किया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सड़कें सुधरी हैं, वह जो पैसा बाकी है, उस पैसे को भी अभी तक आपने नहीं दिया, तो कम से कम कृपा कर दीजिए और जो बकाया है, वह दे दीजिए। जो वायदा करके आए हैं, उसे बाद में भेज दीजिएगा, उसका हम इंतजार करेंगे। आप बकाया को कब तक देंगे, यह बता दीजिए?

†**جناب غلام رسول بلیاوی** : سبھاپتی مہودے، سب سے پہلے تو میں مانینے منتری مہودے کا اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ کی نیت ہے کہ دیں گے کب دیں گے، وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہار کے پل اور این ایچ کی مرمت کے لیے، جب کہ مرکزی سرکار نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ مانینے نتیش کمار جی کی قیادت میں بہار کی سڑکیں سدھری ہیں، وہ جو پیسہ باقی ہے، اس پیسے کو بھی ابھی تک آپنے نہیں دیا ۔ تو کم سے کم مہربانی کردیجیے اور جو بقایا ہے، وہ دے دیجیے۔ جو وعدہ کرکے آئے ہیں، اسے بعد میں بھیج دیجیے گا، اس کا ہم انتظار کریں گے۔ آپ بقایا کو کب تک دیں گے،یہ بتادیجیے ؟

श्री जयंत सिन्हा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि जो धनराशि जानी चाहिए, वह जा रही है या नहीं जा रही है और यह सरकार की कृपा है या नहीं है। मैं फिर से उन्हें एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कृपा की बात नहीं है, यह जिम्मेवारी की बात है। आपकी तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आएगा, आपकी तरफ से यह प्रमाण आएगा कि यह काम हो रहा है, तो **...(व्यवधान)...** सरकार की जिम्मेवारी है कि इसका खर्चा दिया जाए। इसका खर्चा जरूर मिलेगा। **...(व्यवधान)...**

---

†Transliteration in Urdu Script.

अगर रूरल रोड्स की बात करें, ग्रामीण सड़कों की बात करें, तो माननीय सदस्य को बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम है कि उसमें कई हैड्स होते हैं, कुछ हैड्स राज्य सरकार के होते हैं, जिसमें से राज्य सरकार खर्चा करती है, कुछ हैड्स हैं - जैसे "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" है, उसकी पूरी प्रकिया बनी हुई है। जैसे-जैसे उसका सर्टिफिकेट आता है, वैसे-वैसे उसके फंड्स रिलीज़ होते हैं और वे पैसा केन्द्र सरकार से उनको मिलेगा।

जो नेशनल हाइवेज़ हैं, उनका काम तो एन.एच.ए.आई. के माध्यम से किया जाता है। वहां जो ठेकेदार हैं, वे सर्टिफिकेट पेश करते हैं कि यह काम किया गया है और उसके अनुसार उन लोगों को पैसा दिया जाता है। अगर वे काम सही नहीं करते हैं, तो फिर उनका पैसा जरूर रोका जाता है और देखा जाता है कि वे किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके आधार पर फिर फंड्स रिलीज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं माननीय सदस्य जी को फिर कहूंगा कि यह कृपा की बात नहीं है, यह बिजनेस की बात है। आप सही तरीके से काम करेंगे, तो सरकार से आपको पूंजी जरूर मिलेगी।

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2005 से कुछ पथ का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार सरकार से आपके पास आया हुआ है। अभी तक उस राशि को केन्द्र सरकार की ओर से भेजा नहीं गया है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि कब तक वह राशि यहां से विमुक्त हो जाएगी?

श्री जयंत सिन्हाः सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि अगर केन्द्र सरकार की योजनाएं देखें, तो वहां पर दो प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें कि सड़कों के लिए पैसे रिलीज़ किए जाते हैं। वहां पर एक तो "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" है और दूसरी एनएचएआई है। माननीय सदस्य इसके बारे में औपचारिक रूप से हमें लिखित में दे दें और बता दें कि कहां-कहां रुकावट आई हुई है, तो हम लोग उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।

Malpractices in sale of attached properties of loan defaulters

*112. SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government is wary about rising Non Performing Assets (NPA) in Public Sector banks, if so, the action taken for speedy recovery thereof;

(b) whether Government is aware that the attached properties with banks are being sold at very cheap rate due to prevalent malpractices and corruption; and

(c) whether Government would take steps to have and appoint more reliable and responsible property valuers to assess property worth while granting loans and during disposing off attached properties, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.